



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225456  
CG-DL-E-25022021-225456

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942

No. 69]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

मामला सं. एडीडी-ओआई-45/2020

**विषय:** चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एन, एन-डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड (डीसीसी)” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच (वास्तविक मंदी) की शुरूआत।

1. **फा.सं. 6/53/2020-डीजीटीआर.**—मै. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष वास्तविक मंदी का प्राथमिक कारण बताते हुए चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “एन, एन-डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड (डीसीसी)” (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा

“विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन (जिसे आगे याचिका भी कहा गया है) दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक हर्ष है और उसने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

### **विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड जिसे एन, एन-डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड, डीसीसी तथा 1, 3-डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड (डीसीसी) के नाम से भी जाना जाता है, है। डी सी सी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी<sub>6</sub>एच<sub>11</sub>एन)<sub>2</sub>सी है। यह एक हल्के पीले रंग का रंगहीन पदार्थ है जो तरल रूप में या अर्ध ठोस रूप में होता है और उसमें एक मीठी महक होती है। इसका प्राथमिक उपयोग कृत्रिम पैपटाइड सिंथेसिस के दौरान अमीनो अम्ल को जोड़ना है। इस सामग्री का कम गलनांक इसे आसानी से संभालने हेतु पिघलने देता है। यह डाइक्लोरोमिथेन टेट्राहाइड्रोफुरान, एसीटोनाइड्राइल और डाईमिथाइलफोर्माइड में तेजी से घुलता है परंतु जल में नहीं घुलता है और संबद्ध वस्तु के लिए कैमिकल एबस्ट्रक्स सर्विस (सीएएस) पंजीकरण सं. 538-75-0 है।
4. यह उत्पाद मुख्यतः एमीकासीन ग्लूटाथियोन डीहाइड्रेंट्स में तथा एसिड एनहाइड्राइड, एल्डेहाइड, केटोन और आइसोसाइनेट के सिंथेसिस में प्रयुक्त होता है। इसे पेप्टाइड्स, ईस्टर, ईथर, नाइट्राइल्स आदि के सिंथेसिस में भी प्रयोग किया जाता है। यह एंटीरेक्ट्रोवायरल औषधियों जैसे वेलांरिकलोवीर तथा एमीकासीन में प्रयुक्त में कच्ची सामग्री है। डीसीसी चिकित्सा, स्वास्थ्य, प्रसाधन और जैविक उत्पादों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है।
5. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण 29251900, 29252990 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, पीयूसी को अन्य आईटीसी (एचएस) कोडों के तहत भी आयातित किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

### **समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्दिष्टन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग**

7. यह आवेदन मै. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के दावे के अनुसार भारत में समान वस्तु का कोई अन्य विनिर्माता नहीं है। आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत है। आवेदक ने दावा किया है कि वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक से किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं। इसके मद्देनजर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष यह है कि आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

### **संबद्ध देश**

8. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

**जांच की अवधि**

9. आवेदक ने 1 जनवरी, 2020 – 30 जून, 2020 (6 महीने) की जांच अवधि (जिसे आगे “पीओआई” भी कहा गया है) का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 महीने) की पीओआई पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2017- मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019, अप्रैल 2019-दिसंबर, 2019 तथा पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

**कथित पाटन का आधार****सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन की घरेलू लागतों और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की जांच को पास न कर लें। आवेदक ने बताया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के मद्देनजर चीन जन.गण. से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी धारणा बनाई गई है और चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार अधिमानित किया गया है।
11. आवेदकों ने बताया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु के लिए कीमत का कोई ब्यौरा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। आवेदक ने प्रस्ताव किया है कि जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को समान उत्पाद के लिए भारत में प्रदत्त या देय वास्तविक कीमत के आधार पर परिकलित किया जाए। तदनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पादन लागत और बिक्री सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ जोड़कर उसके आधार पर चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

**निर्यात कीमत**

12. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किए गए हैं।

**पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है और घरेलू उद्योग के प्रारंभिक स्तर पर परिणामी वास्तविक मंदी हो रही है।

**वास्तविक मंदी, क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

14. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह आरंभिक स्तर में है और पीयूसी का वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी, 2020 से शुरू हुआ था तथा उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी रही है।
15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है जिससे घरेलू उद्योग वास्तविक रूप से मंदीग्रस्त हुआ है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा भी किया है कि उसकी स्थापना उत्पादन, बिक्री और लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में पीयूसी के ऐसी

कीमत पर आयातों में वृद्धि जो घरेलू उद्योग की क्षतिरहित बिक्री कीमत से कम थी, के परिणामस्वरूप बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी/मौजूदा क्षति हो रही है जिससे घरेलू उद्योग की स्थापना में और अधिक बाधा आई है।

### **पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

16. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर विधिवत रूप से साध्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी/क्षति और कथित पाटन और वास्तविक मंदी/क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक मंदी/क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

### **प्रक्रिया**

17. नियमावली नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg15-dgtr@gov.in](mailto:adg15-dgtr@gov.in) , [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) , [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) तथा [jd14-dgtr@gov.in](mailto:jd14-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

### **समय-सीमा**

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों [adg15-dgtr@gov.in](mailto:adg15-dgtr@gov.in) , [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) , [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) तथा [jd14-dgtr@gov.in](mailto:jd14-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

33. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

### **असहयोग**

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2021

**Case No. ADD-OI-45/2020**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation (Material-Retardation) concerning imports of “N, N-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC) originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/53/2020-DGTR.**—1. M/s Clean Science and Technology Private Limited Ltd (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application (hereinafter also referred to as the “Petition”) seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “N, N’-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)” (hereinafter also referred to as “subject goods” or the “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as “subject country”), citing preliminary reason of material retardation, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and has requested for imposition of the anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**Product Under Consideration (PUC)**

3. The product under consideration in the present application is Dicyclohexylcarbodiimide, also known as N, N’-Dicyclohexyl Carbodiimide, DCC and 1, 3-Dicyclohexylcarbodiimide (DCC), originating in or exported from the subject country. DCC is an organic compound with chemical formula (C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>N)<sub>2</sub>C. It is colourless to pale yellow in colour, occurring in liquid or semi solid form and has a sweet odor. Its primary use is to couple amino acids during artificial peptide synthesis. The low melting point of this material allows it to be melted for easy handling. It is highly soluble in dichloromethane, tetrahydrofuran, acetonitrile and dimethylformamide but insoluble in water and the Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number for the subject goods is 538-75-0.
4. This product is mainly used in amikacin, glutathione dehydrants as well as in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate. It is also used in the synthesis of peptides, esters, ethers, nitriles etc. It is a key raw material in antiretroviral drugs like Valaciclovir and Amikacin. DCC is widely used in medical, health, make-up and biological products.
5. The PUC is classified under the tariff custom classification 29251900, 29252990. The PUC, however, has been also may imported under other ITC (HS) codes. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

**Like article**

6. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject countries.

**Domestic industry**

7. The application has been filed by M/s Clean Science and Technology Private Limited. As per the claim of the Applicant, there is no other manufacturer of the like articles in India. The production by the Applicant constitutes 100% of the domestic production of the like article. The Applicant has claimed that it is not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules. In view of the

same, it is prima facie concluded that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

### **Subject Country**

8. The subject country for this investigation is China PR.

### **Period of Investigation**

9. The Applicant proposed the Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") 1st January, 2020 – 30th June, 2020 (6 months). However, the Authority proposes to consider the POI as 1st January, 2020 to 31st December, 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods April 2017-March 2018, April 2018- March 2019, April 2019-December 2019 and the POI.

### **Basis of alleged dumping**

#### **Normal Value**

10. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited and relied upon Para 8(2) of Annexure I of the Rules and stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicants have claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. The Applicant has stated that for China normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above, subject to rebuttal by the responding exporters from China PR, a presumption has been made regarding non-market economy for China PR and normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.
11. The Applicant has stated that they are not in a position to obtain any price details for the subject goods prevalent in any of the market economy third country. The Applicant has proposed that, for the purpose of initiation, normal value may be constructed on the basis of actual prices paid or payable in India for the like product. Accordingly, the Authority has, for the purpose of initiation, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India and selling, general and administrative expenses along with reasonable addition for profit.

#### **Export Price**

12. The Authority has computed the export price for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

#### **Dumping Margin**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under consideration from the subject country. There is prima facie evidence that the product under consideration from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country and consequent materially retardation to the nascent stage domestic industry.

#### **Material Retardation, Injury and Causal link**

14. The Domestic Industry claimed that it is at the nascent stage and commercial production of PUC was started in January, 2020 onwards and there has been material retardation to the establishment of the industry.
15. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury which has materially retarded the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its establishment has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of PUC at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the material retardation/injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country which further hampered the establishment of Domestic Industry.



**Initiation of Anti-Dumping Investigation**

16. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, material retardation/injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and material retardation/injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the material retardation/injury to the domestic industry.

**Procedure**

17. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**Submission of Information**

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent by email at email address [adg15-dgtr@gov.in](mailto:adg15-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [jd14-dgtr@gov.in](mailto:jd14-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
19. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**Time Limit**

23. Any information relating to the present investigation should be sent by email at the email addresses [adg15-dgtr@gov.in](mailto:adg15-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [jd14-dgtr@gov.in](mailto:jd14-dgtr@gov.in) within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**Submission of information on confidential basis**

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.



29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

33. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

#### **Non-cooperation**

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority